

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रभा गौतम आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 156/2023 (नि.पं.)

पंजीयन दिनांक 08.09.2023

G.C.M.S. NO. :- 2023/156

1-वरदीबाई पत्नी उदाजी जाति जाट, आयु व्यस्क निवासी गीदाखेड़ा तहसील भदेसर

-निगराकारगण

बनाम

1-सूरजबाई पत्नी शान्तिलाल जाति खटीक निवासी मण्डपिया, तहसील भदेसर

2-ग्राम पंचायत मण्डपिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डपिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

-गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 17901 दिनांक 24.07.2023 द्वारा ग्राम पंचायत मण्डपिया, पंचायत समिति भदेसर

उपस्थिति : 1-श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता निगराकारगण

2-श्री गुलशेर अली सैयद, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1

3-श्री मोहम्मद रईस, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2

:: निर्णय ::

दिनांक 23.03.2026

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा गैर निगराकार सूरजबाई के पक्ष में विधि विपरीत प्रक्रिया अपनाते हुए आबादी भूमि के संबंध में विक्रय विलेख दिनांक 24.07.2023 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के विहित प्रावधानों व नियमों के विपरीत होने से निरस्त कराये जाने हेतु यह निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा विपक्षी सूरजबाई को पट्टा संख्या 17901 निलामी की प्रक्रिया से जारी किया जाना बताया है परन्तु पंचायत के सचिव व सरपंच द्वारा मौके पर कोई निलामी बोली नहीं लगायी गयी है और मनमानी कर 323/ रूपये से गणना कर पट्टा जारी कर दिया है, कोई मिसल दर्ज नहीं की, कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया, वार्ड पंचों की कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण नहीं किया, पट्टे में आ.सं. 1622/189 की भूमि का पट्टा जारी किया जाना बताया परन्तु पट्टे में पडौस एक किलोमीटर दूर जमीन के बताये हैं। निगराकार द्वारा भूखण्ड आ.सं. 439 मी. खरीद रखा है जो वर्तमान में आबादी है और निगराकार का भूखण्ड बरसाती नाला व



सांवलिया जी मण्डपिया की मुख्य सड़क से अटैच है। नाले व मुख्य सड़क के पास कोई जमीन खाली नहीं बचती है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आनन फानन में पडौस निगराकार की जमीन के पास के लिख दिये, इस कारण गैर निगराकार की फर्जी पट्टे की आड़ में प्रार्थी के भूखण्ड पर कब्जा करना चाहती है और मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। चूंकि पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य कोई जमीन मौके पर नहीं है और न ही गैर निगराकार का कब्जा है फिर भी गैर निगराकार फर्जी पट्टे के आधार पर मौके पर कब्जा करना चाहती है एवं भारी विवाद उत्पन्न हो गया है, इस कारण पट्टा अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलशेर अली सैयद ने तथा गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रईस ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। ग्राम पंचायत, मण्डपिया से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि की दर 323/ रुपये की गणना कर जारी कर दिया, मौके पर कोई निलामी बोली नहीं लगायी गयी जबकि उक्त भूमि मुख्य सड़क मार्ग से अटैच होने से दर काफी अधिक है और 96,600/ रुपये की राशि जमा कर पट्टा जारी कर दिया जो पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं है और अनुमोदन पंचायत समिति से नहीं कराया गया। गैर निगराकार को पट्टा आराजी नंबर 1622/189 पर जारी किया जाना बताया है जबकि पडौस आराजी नंबर 439 व इस जमीन को व्यवसायिक रूपांतरण कराते समय सड़क से 80 फीट छोड़ी गयी जमीन के बता दिये गये हैं। इस प्रकार पट्टा किसी भी तथ्यों से मेल नहीं खाता है और विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार का पट्टा बहाल रहने से निगराकार को भारी अकथनीय नुकसान होगा, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा षडयंत्र स्वकर नियमों के विरुद्ध जाकर गैर निगराकार को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से एवं निगराकार को क्षति पहुंचाने की नियत से अवैध पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त पट्टा विधि-विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची के संलग्न विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदोसर द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/पसभ/पंचायत/जांच/2024-25/132 दिनांक 18.06.2024 में अंकित तथ्यों अनुसार बताया कि जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 18.06.2024 के अनुसार ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 (1) (2) के तहत विक्रय विकलेख प्रारूप 167 (1) में जारी किये गये हैं जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 (2) (घ) के अनुसार अन्य जिला सड़क की मध्य रेखा से 50 फीट की दूरी नहीं छोड़कर नियमों के विपरीत जारी किये गये हैं। अतः उक्तानुसार पट्टा निरस्त योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर पंचायत राज अधिनियम के विहित प्रावधानानुसार गैर निगराकार संख्या 01 को जो पट्टा जारी किया गया है वह विधिवत होकर कानूनन सही जारी किया गया है जिसके संबंध में निगराकार ने अनुचित रूप से निगरानी प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए नियमानुसार पात्र व्यक्ति को पंचायती राज अधिनियम के अनुसार विधिवत जांच करते हुए पंचायती कोरम में पंचायत द्वारा निर्मित कमेटी के मौका निरीक्षण व विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया है जिसे प्रार्थिया निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं रखती है। पंचायत की आबादी भूमि आराजी नं. 448 रकबा 0.94 हैक्टेयर गै.मु.आबादी में जारी किया गया है जिसके पडौसान भी भौतिक रूप से सही अंकित किये गये हैं। आराजी नंबर 439 मी. निगराकार द्वारा खरीदने का तथ्य



जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। निगराकार को पंचायत द्वारा पट्टा कब जारी किया गया उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है तथा निगराकार मुझ उत्तरदाता पट्टाधारी के कोई पडौसी भी नहीं है फिर भी गैर निगराकार को मानसिक परेशान करनेके लिये यह निगरानी पेश की है। पट्टेशुदा भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य बाबत दिनांक 09.08.2023 को निर्माण स्वीकृति भी जारी कर रखी है साथ ही स्वयं निगराकार अपना भूखण्ड/आराजी नंबर 439 में होना बता रही है, दोनों ही आराजियात भिन्न भिन्न है, पट्टे के पडौसान भी अलग अलग हैं मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वक्त पंजीयन के विपक्षी सं. 2 एवं विकास अधिकारी द्वारा पट्टे पर आबादी आराजी नंबर 1622/189 अंकित किये गये परन्तु उक्त भूखण्ड आबादी की आराजी नंबर 448 में स्थित होने से उक्त पंजीयन का शुद्धि पत्र द्वारा पट्टा पंजीयन आराजी नंबर 1622/189 अंकन को सुधारते हुए पूरक दस्तावेज शुद्धि पत्र पट्टा पंजीयन **Lease Deed for Local Bodies (Patta)** विपक्षी संख्या 1 व 2 की आपसी सहमति से शुद्ध करा पंजीयन करा दिया गया था जिससे आराजी नंबर 1622/189 के स्थान पर आराजी नंबर 448 पढा जाने का शुद्धि पत्र दिनांक 21.08.2023 को किया, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा निगरानी में उठाये गये तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से निगरानी निरस्तनीय है। निगराकार जो अन्य पिछड़ा वर्ग की सम्पन्न महिला है, गैर निगराकार जो कि अनुसूचित जाति की गरीब महिला है उसे प्रताडित करने की गरज से मिथ्या कथनों पर निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त किया जाने योग्य है। प्रार्थी /गैर निगराकार ने उक्त प्रकरण की निगरानी में न्यायालय आपमें जवाब प्रस्तुत कर दिया तत्पश्चात गैर निगराकार रोडीलाल द्वारा एक एस.बी.सिविल रीट पिटिशन नंबर 12531/2024 माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की जिसे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 16.08.2024 को स्वीकार फरमा माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (ए.डी.एम) चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया कि उक्त निगरानी पन्नालाल बनाम सुशीला देवी रीट नंबर 108/2006 डिसाइड ऑन 12.02.2008 के निर्णय को मद्देनजर रखते हुऐ निर्णय पारित करें एवं एक निर्णय कुशालसिंह बनाम सरकार रीट पिटिशन नंबर 57/2020 निर्णय दिनांक 14.01.2020 है। उक्त निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी श्रीमान् के न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त निगरानी में अपील के प्रावधान है जो धारा 61 के तहत दिये गये हैं ऐसी सूरत में उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही न्यायालय गैर निगराकार के ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुऐ निगरानी खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रश्नगत अपील के संदर्भ में हमने पट्टा पत्रावली, अपील, जवाब अपील एवं बहस में प्रस्तुत कथनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :-

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudicial to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.



(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any person interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec. (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Subsec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्हीं भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये हैं। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं। हमने नियम 158 व 159 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

158. Allotment of lands to weaker sections.-

- (1) The Panchayat may allot Abadi land up to [300 sq. yards] in village Abadis at concessional rate to members of Scheduled Caste, scavengers, Scheduled Tribes, Backward Classes, village artisans, landless persons dependent on wage labour, IRDP selected families, Handicapped, Nomadic Tribes, Gadia Lohar who do not own house sites/house and also to flood victims whose house have been washed away or the house sites have been rendered unfit for future habitation due to floods [and patta of such land may be issued in Form XXIII-C] [IA. the Panchayat may allot abadi land upto [300 Sq. Yards] in village Abadi at concessional rate to ex-service men in bordering Panchayat Samiti areas.]

(1)	Rates to be charged from such allottees will be as under :	
(a)	In villages having population less than 1000 (1991 census).	Rs. 2/- per sqr. mtr.
(b)	In villages having population from 1001 to 2000 (1991 census).	Rs. 5/- per sqr. mtr. 2000
(c)	In villages having population more than 2000 (1991 census).	Rs. 10/- per sqr. mtr.

Provided that the State Government may allot such lands free of charges to any such category of persons.

[Provided further that in case of allotment of abadi land to the families of below poverty line, the Panchayat may allot the land free of charge.]

- [(2-A) The Panchayat may allot Abadi land upto 300 Sq. Yards free of charge to nomadic sheep rears.]

- [(2-B) The State Government may allot Abadi land to oustees of irrigation project, equal to the house sites or house owned by them subject to maximum of 300sq. yards free of charge.]



प्रकरण संख्या 156/2023 (नि.पं.)
वरदीबाई पत्नी उदा जाट निवासी गीदाखेड़ा बनाम सूरजबाई पत्नी शांतिलाल खटीक निवासी मण्डफिया

- (2) Abadi land allotted free of charge shall be non-transferable. A seal in block letters "NOT FOR SALE" shall be affixed on the face of all such Pattas. In case any allottee transfers or sells such house site/house to any other persons, allotment shall stand cancelled, ownership shall vest in the Panchayat along with construction or material lying thereon and transferee will be ejected to trespasser on such Abadi Land.
- [(3A) Thirty percent of Land allotted under this rule shall be allotted to widows and divorce women.]
- (4) Panchayat may however by a resolution in the meeting, decide to allot such land by negotiation to such trespasser on market price on compassionate grounds.
- (5) The allottee shall be debarred from any subsequent allotment in future
- (6) Provisions contained in Sub-rules (3), (4) and (5) shall also be applicable for shop sites allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes etc., in Panchayat areas.
- (7) For allotment of houses sites to flood victims at another place/places, the Panchayat concerned shall invite applications from such persons along with an undertaking that in case of allotment of house sites at another place/places, the house sites washed away in flood along with material shall vest in the Panchayat concerned free from all encumbrances.

159. **Allotment of lands on concessional price.-**

- (1) The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.
- [(2) The Panchayat may also allot plots upto 1500 sq. yards in abadi area, on priority basis, for construction of godowns/ offices to-
- (i) Primary Agricultural Cooperative Society/Large Sized Multipurpose Marketing Society, at 50% of the Market price as mentioned in sub-rule (5) of Rule 152;
- (ii) Gram Sewa Sahakari Samiti or Kray Vikary Sahakari Samiti, free of charge subject to confirmation by the State Government.]

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियम 140 से नियम 159 तक में भूखण्ड नीलामी के प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये हैं, जो कि बाध्यकारी है। नियम 141 में प्रावधित किया गया है कि भूमि का विक्रय साधारणतया नीलामी के माध्यम से किये जायेंगे जब तक की ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हो। पंचायत ऐसी भूमियों का अग्रिम रूप से नियत किये गये नीलामी कार्यक्रम के माध्यम से विक्रय करने का विनिश्चय कर सकेगी। नियम 142 के तहत आबादी के विकास के लिए भूमि पंचायत को अंतरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए स्कीमें अनुमोदित विकास योजना के अनुसार तैयार की जायेगी। ऐसी स्कीमों का क्रियान्वयन अनुमोदित प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। नियम 143 में आबादी क्षेत्रों में भूखण्डों के नीलामी के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। नियम 145 के तहत आबादी भूमि या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो। नियम 146 के तहत तीन पंचों की कोई समिति 15 दिवस के भीतर-भीतर स्थल का निरीक्षण कर आवेदित विक्रय की



वांछनीयता को संबंध में पंचायत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नियम 147 के तहत पंचायत बैठक में अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करेगी कि प्रस्तावित विक्रय किया जाय या नहीं। नियम 148 के तहत पंचायत अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाये तो वह उप-नियम 2 में अधिकथित रीति से प्रपत्र 22 में नोटिस प्रस्तावित विक्रय के संबंध में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। नियम 148 के तहत आमंत्रित आक्षेपों का नियम 149 के तहत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए निपटारा किया जावेगा। नियम 150 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमि के किसी ऐसी तारीख को जो संकल्प के आदेश की तारीख से एक मास से पूर्व की न हो, और विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समय और स्थान पर नीलाम का आदेश देगी। नियम 151 के तहत नीलामी समिति का गठन किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 152 के तहत बाजार कीमत का प्रावधान प्रावधित है। नियम 154 के तहत बोली की स्वीकृति विहित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यक्षीन होगी। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्गों के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह-स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उप-नियम 2 में वसूली योग्य दरे प्रावधित की गई है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। उप-नियम 3 के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बडे अक्षरों में “विक्रय के लिए नहीं” की मुहर लगाई जायेगी। नियम 159 में भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विक्ता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं है) जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है, नियम 152 के उप-नियम (5) में उल्लिखित बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 167 (1) में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ‘ नियम 153 में उपबंधितानुसार संदाय कर दिये जाने, नियम 154 में उपबंधितानुसार विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने और नियम 166 के अधीन अपील, यदि कोई हो, निपटा दिये जाने, या यदि कोई भी अपील नहीं की गई हो तो उसके लिए विहित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाला प्रारूप 23 में लिखा गया एक विलेख पंचायत की ओर से निष्पादित किया जायेगा।’ उक्त नियमों के नियम 161 -(2) (ग) में निर्देश हैं कि पंचायत ‘राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से पचहत्तर फुट’ एवं 161 -(2)(घ) में निर्देश हैं कि ‘अन्य जिला सड़कों और गांव की सड़कों की मध्य रेखा से पचास फुट’ की सीमाओं में न तो किसी आबादी भूमि का विक्रय करेगी न ही पक्का संनिर्माण अनुज्ञात किया जायेगा। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.07.2023 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत, मण्डपिया द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकारगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत, मण्डपिया द्वारा उक्त विवादित पट्टा स्वयं की आबादी भूमि पर, बिना निलामी प्रकिया किये, पट्टे के पडौस एक किलोमीटर दूर बताये जाने, भूखण्ड बरसाती नाले व सडक के अटेच होना बताया है। विकास अधिकारी, पंचायत



समिति, भदेसर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.06.2024 से जारी पट्टा सड़क सीमा से निर्धारित दूरी नहीं छोड़कर जारी किया जाने की पुष्टि होती है।

निगराकारगण द्वारा अपनी निगरानी में यह तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना मौका निरीक्षण किये, पडौस एक किलोमीटर दूर अंकित कर दिये हैं, भूखण्ड बरसाती नाला व मुख्य सड़क से अटेच होने से कोई भूमि खाली नहीं है। अधिवक्ता निगराकारगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को गलत तरीके से नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत मण्डपिया पंचायत समिति भदेसर द्वारा विवादित पट्टा संख्या 17901 दिनांक 24.07.2023 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 17901 दिनांक 24.07.2023 जो कि गैर-निगराकार श्रीमती सूरजबाई पत्नी शान्तिलाल खटीक निवासी मण्डपिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़